सन् 2000 तक भूमि की प्रति-व्यक्ति आवश्यकता के संबंध में कोई आकलन किया है; और

(घ) भूमि की उपलब्धता में कमी होने की इस प्रवृति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम): (क) जी हां।

(ख) 31 मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार देश में और गुजरात राज्य में कुल भूमि की प्रति व्यक्ति उपलब्धता क्रमश: 0.36 और 0.45 हैक्टेयर होने का अनुमान है;

(ग) भूमि की प्रति व्यक्ति जरूरत के संबंध में अनुमान नहीं लगाया जाता क्योंकि यह बहुत से घटकों पर निर्भर है जिसमें जनसंख्या का आकार, भूमि की उपलब्धता, भूमि की उत्पादकता, भू-उपयोग आदि शामिल हैं।

(घ) देश में जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं?

**ICDS in Madhya Pradesh**

2468. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the number of blocks of Madhya Pradesh, where the Integrated Child Development Scheme has been sanctioned and in how many it remains to be sanctioned; and

(b) what are the impediments in sanctioning this scheme in the remaining blocks and by when all the blocks are proposed to be covered by this scheme?

THE MINSITER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMEN (DEPTT. OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT) (SMT. BASAVARAJESHWARI): (a) The Integrated Child Development Services (ICDS) Scheme has been sanctioned in 315 Community Development (CD) Blocks in the State of Madhya Pradesh. As on date, 144 CD Blocks in the State of Madhya Pradesh are not covered under the ICDS Scheme.

(b) Of the remaining 144 CD Blocks, 18 CD Blocks have already been approved for the year 1996-97 under the World Bank-assisted ICDS-II Project. Since the Government is committed to universalise the ICDS Scheme at the earliest, the remaining 126 CD Blocks in the State will be covered during the current year and in the coming years, depending on the availability of resources for expansion of the ICDS Scheme each year.

**सरकार द्वारा वैद्यनाथन समिति की रिपोर्ट पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई**

2469. श्री राम चेठमलानी:
श्रीमती सुषमा स्वराज:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैद्यनाथ समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को वर्ष 1992 में सौंप दी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त रिपोर्ट का अध्ययन करने हेतु विशेषज्ञ अधिकारियों से युक्त किसी समिति का गठन किया था;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) क्या समिति की रिपोर्ट में सरकार ने सिंचाई सेवाओं में सुधार लाने और सिंचाई सेवाओं पर वहन किए जाने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया गया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू): (क) से (ङ) जी हां, चूंकि सिंचाई राज्यों का विषय है, इसलिए, वैद्यनाथन समिति की रिपोर्ट सहित अधिकारियों के दल की सिफारिशें फरवरी 1995 में योजना आयोग द्वारा सभी राज्य सरकारों को विचार तथा आगे कार्रवाई की लिए भेजी गई हैं।

**Production of MICA in the country**

2470. SHRI DIGVIJAY SINGH: Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a) whether there has been an alarming drop in the production of Mica in the country;

(b) whether Government have taken steps to improve its production; and

(c) if so, the details thereof stating the efforts made by Government to improve the situation?